IMPACT FACTOR 7.50 (SJIAI)

BIHAR SHODH SAMAAGAM

Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 3 July-September, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
https://doi.org/10.5281/zenodo.23168692

ISSN : 3048-6971

"भारत में रेशम उत्पादों के निर्यात एवं विदेशी मुद्रा अर्जन में योगदान का तुलनात्मक अध्ययन"

1* डॉ. लखेश्वर
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य)
शासकीय राम भजन राय एन.ई.एस.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर (छ.ग.)

2 अंकित कुमार अग्रवाल**
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य)
शासकीय महात्मागांधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, खरसिया जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

3* रितेश पटेल**
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य)
नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, सारंगढ़
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

सारांश

भारत में रेशम उद्योग वन एवं कृषि आधारित उद्योग है। रेशम उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, जो भारत के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करता है। यह अध्ययन भारत में रेशम तथा रेशम–आधारित उत्पादों के निर्यात की संरचना, प्रवृत्ति और विदेशी मुद्रा अर्जन में उनके योगदान का विश्लेषण करता है। अध्ययन की मुख्य समय–सीमा वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25 है, उपलब्ध नवीनतम व्यापक वस्त्र–निर्यात आँकड़ों के माध्यम से 2025–26 की स्थिति को अलग से प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान का आधार वस्त्र मंत्रालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड और विदेश व्यापार से संबंधित सरकारी सांख्यिकी हैं। प्रतिशत परिवर्तन, उत्पादवार हिस्सेदारी और निर्यात–आयात अंतर का गणना–आधारित विश्लेषण किया गया है।

केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संकलित विस्तृत श्रृंखला के अनुसार रेशम एवं संबंधित वस्तुओं का निर्यात 2020–21 में ₹1,466.60 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹2,361.75 करोड़ हुआ। इसी अवधि में संबंधित आयात ₹759.75 करोड़ से ₹1,561. 77 करोड़ हुआ , वर्ष 2024–25 में निर्यात–आयात अंतर ₹799.98 करोड़ रहा। कपड़े एवं मेड–अप्स उत्पादों का निर्यात मूल्य में सबसे बड़ा योगदान है। इसके विपरीत, वस्त्र मंत्रालय की संकीर्ण "silk products" वर्गीकरण–श्रृंखला 2025–26 में ₹2,262 करोड़ निर्यात दिखाती है, विभिन्न उत्पाद–सीमाओं के कारण इसे व्यापक श्रृंखला के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा गया है। निष्कर्ष यह है कि गुणवत्तापूर्ण कच्चे रेशम, प्रसंस्करण, पहचान–आधारित विपणन, निर्यात विविधीकरण और छोटे उत्पादकों की मूल्य–श्रृंखला में सहभागिता से विदेशी मुद्रा अर्जन की क्षमता अच्छा की जा सकती है।

मुख्य शब्द – रेशम उद्योग, रेशम उत्पाद, निर्यात, विदेशी मुद्रा, वस्त्र उद्योग, केंद्रीय रेशम बोर्ड, DGCI&S.

1. प्रस्तावना– विश्व के रेशम उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है तथा भारत में रेशम के विभिन्न प्रजातियों के रेशम का उत्पादन होने से भारत अपना विश्व के स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रेशम भारत की प्राकृतिक रेशों पर आधारित वस्त्र–अर्थव्यवस्था का विशिष्ट घटक है। भारत में प्रमुखतः चार प्रकार के रेशम पाए जाते हैं शहतूती (मल्बेरी), कोसा(तसर), एरी और मूंगा रेशम के साथ भारत में पालन, धागाकरण, बुनाई, रंगाई, परिधान निर्माण तथा विपणन की अनेक परस्पर जुड़ी गतिविधियों संचालित होती हैं। रेशम की आर्थिक प्रासंगिकता केवल कपड़े की बिक्री तक सीमित नहीं है, इसमें कृषि–आधारित कच्चे माल, कुटीर एवं लघु विनिर्माण, डिजाइन, हस्तकला तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संबंध दिखाई देता है। वस्त्र मंत्रालय (2025a) ने भारत को विश्व के प्रमुख रेशम उत्पादकों में स्थान दिया है और 2023–24 के लिए 38,913 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया है।

रेशम उत्पाद उच्च मूल्य–वर्धन वाले परिधानों, कपड़ों, मेड–अप्स और कालीनों के रूप में निर्यात किए जा सकते हैं। इसलिए निर्यात के मूल्य को केवल उत्पादित कच्चे रेशम की मात्रा से नहीं समझा जा सकता। किस प्रकार के तैयार उत्पाद विदेशी ग्राहक खरीदते हैं, उत्पादन में आयातित धागे की भूमिका क्या है, और विभिन्न वर्षों में मूल्य–श्रृंखला का स्वरूप

किस दिशा में बदलता है – ये आर्थिक प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी संदर्भ में रेशम का निर्यात क्षेत्रीय आजीविका और विदेशी मुद्रा प्राप्ति के बीच एक संभावित सेतु बनता है (Dasari et al.,2024)।

वस्त्र मंत्रालय (2025b) के अनुसार व्यापक वस्त्र एवं परिधान निर्यात, हस्तशिल्प सहित, 2024–25 में 37,754.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस बड़े व्यापारिक परिदृश्य में रेशम की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी अपेक्षाकृत छोटी है, फिर भी इसके अलग उत्पादन–आधार, विशिष्ट ब्रांड–पहचान और प्रसंस्कृत उत्पादों के कारण उसकी संरचना का पृथक अध्ययन आवश्यक है। उद्योग की वास्तविक प्रगति समझने के लिए यह भी देखना होगा कि कच्चे रेशम का आयात घट रहा है या नहीं तथा किस उत्पाद श्रेणी से निर्यात आय बन रही है।

1.1 अध्ययन की प्रासंगिकता

इस शोध की प्रासंगिकता तीन स्तरों पर है। प्रथम, निर्यात से प्राप्त डॉलर–मूल्य भारत की बाह्य व्यापार प्राप्तियों का एक माप प्रदान करता है। द्वितीय, उत्पादवार विभाजन बताता है कि निर्यात नीति और उद्यमों की निवेश–प्राथमिकताएँ कच्चे माल की बिक्री के बजाय किन मूल्य–वर्धित उत्पादों पर केंद्रित हो सकती हैं। तृतीय, आयात के साथ तुलना करने पर सकल निर्यात–वृद्धि और व्यापार–अंतर के बीच अंतर स्पष्ट होता है। ऐसा भेद किए बिना ''विदेशी मुद्रा अर्जन'' को राष्ट्रीय शुद्ध आय या व्यापार लाभ के समान मान लेना अनुचित होगा।

2. साहित्य समीक्षा एवं अवधारणात्मक आधार

Dasari, Venkataramana और Nandini (2024) ने भारतीय रेशम और रेशम उत्पादों के व्यापार में प्रकट तुलनात्मक लाभ का अध्ययन किया। उनके विश्लेषण में रेशम धागे, रेशम अपशिष्ट और बुने हुए कपड़ों की कुछ श्रेणियों में तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेत मिला, जबकि कच्चे रेशम की कुछ श्रेणियों में ऐसी स्थिति नहीं थी। उनका शोध दर्शाता है कि एकीकृत ''रेशम निर्यात'' के बजाय उत्पाद–स्तरीय अध्ययन अधिक सूचनात्मक है। तथापि उनके अध्ययन की समय–सीमा और इस शोध में प्रयुक्त नवीनतम सरकारी वार्षिक आँकड़े अलग है, इसलिए यहाँ उनके निष्कर्षों को वर्तमान वर्षों की सीधी पुष्टि नहीं माना गया है।

केंद्रीय रेशम बोर्ड (2025) की निर्यात–आयात तालिका 2020–21 से 2024–25 के लिए कोकून, कच्चा रेशम, धागा, कपड़े एवं मेड–अप्स, तैयार वस्त्र, कालीन और रेशम अपशिष्ट की पृथक जानकारी देती है। इसकी विशेष उपयोगिता यह है कि एक ही उत्पाद–समूह के लिए भारतीय रुपये और मिलियन अमेरिकी डॉलर दोनों में राशि दी गई है। इससे प्रवृत्ति, उत्पाद संरचना और व्यापार–अंतर का तुलनीय विश्लेषण किया जा सकता है। वस्त्र मंत्रालय (2025b) की समग्र वस्त्र श्रृंखला व्यापक वस्त्र अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि उपलब्ध कराती है, पर उसकी "silk products" श्रेणी को केंद्रीय रेशम बोर्ड की विस्तृत श्रेणी का समतुल्य नहीं माना जा सकता।

आर्थिक सर्वेक्षण (भारत सरकार, 2025) बताता है कि वस्त्र उद्योग व्यापक विनिर्माण एवं रोजगार व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके आधार पर रेशम के निर्यात का अध्ययन व्यापक वस्त्र–आधारित औद्योगिकीकरण के संदर्भ में किया जा सकता है, किंतु राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रतिशत को स्वतः रेशम उद्योग पर लागू नहीं करना चाहिए। वस्त्र मंत्रालय (2026) द्वारा प्रकाशित 2025–26 के ऑकड़े हाल की दिशा स्पष्ट करते हैं, लेकिन 2020–21 से 2024–25 की विस्तृत रेशम श्रृंखला से उनका सांख्यिकीय दायरा भिन्न है।

2.1 अनुसंधान अंतर

उपलब्ध नीति–रिपोर्ट प्रायः उत्पादन, योजनाओं या कुल निर्यात पर केंद्रित हैं, प्रतिस्पर्धात्मकता–संबंधी शोध अक्सर पूर्ववर्ती समयखंडों का अध्ययन करते हैं। इस शोध का योगदान एक अद्यतन, सीमित किन्तु पारदर्शी तुलनात्मक ढांचे में निर्यात–मूल्य, आयात–मूल्य, प्रमुख उत्पाद–समूह और हाल की वर्गीकरण–संबंधी सावधानियों को साथ पढ़ना है। यह नवीन प्राथमिक सर्वेक्षण या वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का स्वतंत्र अनुमान नहीं है।

3. शोध उद्देश्य

(1) 2020–21 से 2024–25 के दौरान भारत के रेशम एवं संबंधित उत्पाद निर्यात के मूल्य में परिवर्तन का अध्ययन ।
(2) उत्पादवार निर्यात संरचना की पहचान ।
(3) संबंधित आयात के साथ तुलना कर व्यापार–अंतर का आकलन।
(4) वस्त्र क्षेत्र के भीतर रेशम उत्पादों के हिस्से को उपयुक्त वर्गीकरण में स्पष्ट करना
(5) उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्यात–वृद्धि हेतु व्यावहारिक सुझाव देना।

4. परिकल्पना

H_0– 2020–21 से 2024–25 के मध्य भारत में रेशम उत्पादों के निर्यात में कोई महत्वपूर्ण दीर्घकालीन वृद्धि प्रवृत्ति नहीं है।
H_1 – 2020–21 से 2024–25 के मध्य भारत में रेशम उत्पादों के निर्यात में कोई महत्वपूर्ण दीर्घकालीन वृद्धि प्रवृत्ति है।

5. शोध प्रश्न एवं पद्धति

5.1 शोध प्रश्न

1. क्या अध्ययन–अवधि में रेशम एवं संबंधित उत्पादों का निर्यात मूल्य बढ़ा?
2. क्या तैयार कपड़े एवं मेड–अप्स अन्य श्रेणियों की तुलना में बड़ा निर्यात अंश रखते हैं?
3. कुल निर्यात बढ़ने के साथ संबंधित व्यापार–अंतर में क्या परिवर्तन हुआ?
4. व्यापक वस्त्र–सांख्यिकी का प्रयोग करते समय किन वर्गीकरण–गत सावधानियों की आवश्यकता है?

5.2 शोध डिजाइन और आँकड़ा–स्त्रोत

अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। मूल उत्पादवार आँकड़े वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संकलित निर्यात–आयात विवरण से लिए गए हैं, जिसका घोषित मूल स्रोत – Directorate General of Commercial Intelligence & sladictics (DGCI&S) कोलकाता है। (केंद्रीय रेशम बोर्ड, 2025)। समग्र वस्त्र तुलनाओं और 2025–26 की अतिरिक्त स्थिति के लिए वस्त्र मंत्रालय के आधिकारिक संसदीय उत्तरोंध्प्रेस विज्ञप्तियों को लिया गया है (वस्त्र मंत्रालय, 2025b, 2026)।

3.4 विश्लेषण की विधि

प्रतिशत परिवर्तन = [(वर्तमान वर्ष का मूल्य – पिछले वर्ष का मूल्य)/पिछले वर्ष का मूल्य] ×100, उत्पाद हिस्सेदारी = (संबंधित उत्पाद का निर्यात मूल्य/उसी श्रृंखला का कुल निर्यात) × 100, व्यापार–अंतर = निर्यात मूल्य – आयात मूल्य। डॉलर मूल्य को यथावत मिलियन अमेरिकी डॉलर में और रुपये को करोड़ रुपये में रखा गया है। विभिन्न वर्षों के डॉलर तथा रुपये को किसी स्थिर विनिमय दर से रूपांतरित नहीं किया गया। प्रस्तुत संकेतक वर्णनात्मक हैं, छोटे समय–क्रम के कारण प्रतिगमन या कारणात्मक परीक्षण नहीं किया गया।

3.5 सीमाएँ

1. यह शोध निर्यात प्राप्तियों के सकल आँकड़ों पर आधारित है, न कि निर्यातकों को वास्तव में प्राप्त या देश में रोकी गई शुद्ध विदेशी मुद्रा पर। व्यापार–अंतर में सेवाओं, अन्य क्षेत्रों, घरेलू लागत, आयातित इनपुट की वास्तविक उपयोग–मात्रा या निर्यात लाभांश का समायोजन नहीं है। वर्तमान–दर पर दर्ज रुपये मूल्य में मात्रा, कीमत और विनिमय दर सभी का प्रभाव संभव है, अलग मात्रा–श्रृंखला उपलब्ध न होने से उनकी स्वतंत्र पहचान नहीं की गई है।
2. अध्ययन की अवधि 2020–21 से 2024–25 कुल 5 वर्ष की वित्तीय वर्ष है।

6. भारतीय रेशम निर्यात की पाँच–वर्षीय प्रवृत्ति

तालिका 1 केंद्रीय रेशम बोर्ड की व्यापक रेशम एवं संबंधित वस्तु–श्रृंखला प्रस्तुत करती है। 2020–21 का निम्न आधार, 2021–22 की बहाली, 2022–23 की कमी और उसके बाद वृद्धि स्पष्ट है। कुल डॉलर–मूल्य को विदेशी मुद्रा अर्जन का एक सीमित सकल संकेतक माना गया है (केंद्रीय रेशम बोर्ड, 2025)।

तालिका 1. रेशम एवं संबंधित वस्तुओं का कुल निर्यात, 2020–21 से 2024–25

वित्त वर्ष	निर्यात (₹करोड़)	निर्यात (USD मिलियन)	वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि (%)
2020-21	1466.60	198.30	-
2021-22	1848.96	248.56	26.07
2022-23	1773.38	220.58	-4.09
2023-24	2027.56	244.27	14.33
2024-25	2361.75	297.32	16.48

(स्त्रोतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड 2025, DGCI&S से संकलित आँकड़े)

वृद्धि की गणना रुपये में निर्यात मूल्य पर की गई है। पांच वर्षों में रुपये के आधार पर निर्यात में कुल ₹895.15 करोड़ अथवा लगभग 61.04% की वृद्धि हुई। डॉलर–श्रृंखला में 198.30 से 279.32 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 40.86% की वृद्धि दिखाई देती है। दोनों वृद्धि दरों में अंतर विनिमय दर और मूल्यांकन के प्रभाव की संभावना दर्शाता है, किंतु केवल इन आँकड़ों से उसके स्वतंत्र परिमाण का निर्धारण नहीं किया जा सकता। 2022–23 में गिरावट यह भी स्पष्ट करती है कि बढ़ती अंतिम प्रवृत्ति को निरंतर या बाधारहित वृद्धि नहीं कहा जाना चाहिए।

2024–25 में निर्यात 2023–24 से ₹334.19 करोड़ अधिक रहा। उपलब्ध श्रेणीवार विवरण दर्शाता है कि इस बदलाव को समझने के लिए समग्र वृद्धि के साथ उत्पादों की भागीदारी देखना जरूरी है कपड़े एवं मेड–अप्स के निर्यात ने सकारात्मक योगदान दिया, जबकि रेशम अपशिष्ट के मूल्य में कमी आई। इसके कारण नीति का लक्ष्य केवल किसी एक साल के सकल निर्यात रिकॉर्ड तक सीमित नहीं होना चाहिए।

7. उत्पादवार निर्यात संरचना और मूल्य–वर्धन

उत्पाद–समूहों के बीच अंतर निर्यात की प्रकृति समझने में सहायक है। तालिका 2 में प्रत्येक श्रेणी का 2024–25 का मूल्य और कुल ₹2,361 75 करोड़ में अनुमानित हिस्सा दिया गया है। प्रतिशत को दो दशमलव तक गोल करने से कुल योग में नगण्य अंतर संभव है (केंद्रीय रेशम बोर्ड, 2025)।

तालिका 2. वर्ष 2024–23 में रेशम निर्यात का उत्पादवार संघटन

उत्पाद श्रेणी	निर्यात (₹करोड़)	हिस्सा (%)
कच्चा रेशम	25.42	1.08
रेशम धागा	42.17	1.79
कपड़े एवं मेड–अप्स	1443.98	61.14
तैयार परिधान	486.31	20.59
रेशमी कालीन	99.21	4.20
रेशमी अपशिष्ट	264.66	11.21
कुल	**2361.75**	**100.00**

(स्त्रोतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड 2025, DGCI&S से संकलित ऑकड़े)

कपड़े एवं मेड–अप्स (61.14%) तथा तैयार परिधान (20.59%) मिलाकर निर्यात का लगभग 81.73% बनाते हैं। यह रचना दिखाती है कि उपलब्ध विस्तृत श्रृंखला में भारत की प्रमुख निर्यात प्राप्ति कच्चे रेशम के बजाय प्रसंस्कृत और तैयार वस्तुओं से होती है। हालांकि ''अधिक हिस्सेदारी'' अपने–आप में अधिक घरेलू मूल्य–संवर्धन का निश्चित प्रमाण नहीं है, क्योंकि आयातित धागे एवं अन्य इनपुट की मात्रा इस तालिका में निर्धारित नहीं है।

कपड़े एवं मेड–अप्स का मूल्य 2023–24 के ₹1,119.13 करोड़ से 2024–25 में ₹1,443.98 करोड़ हुआ, तैयार परिधानों का ₹443.79 करोड़ से ₹486.31 करोड़ हुआ। दूसरी ओर अपशिष्ट ₹317.66 करोड़ से घटकर ₹264.66 करोड़ आया। इसलिए कुल वृद्धि की व्याख्या समस्त रेशम–वस्तुओं में समान उछाल के रूप में करना सही नहीं होगा। उत्पाद विविधीकरण में डिजाइन, रंग–स्थिरता, मानकीकरण, समय पर डिलीवरी और मूल्य–वर्धित निर्माण निर्णायक व्यावसायिक पहलू हो सकते हैं।

8. विदेशी मुद्रा अर्जन , आयात और व्यापार – अंतर

विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए डॉलर में सकल निर्यात उल्लेखनीय है, लेकिन राष्ट्रीय व्यापार योगदान को समझने के लिए उसी समूह का आयात भी देखना चाहिए। निर्यात के आँकड़े समस्त विदेशी मुद्रा की शुद्ध उपलब्धता नहीं बताते। तालिका 3 में एक ही आधिकारिक व्यापक वर्गीकरण के निर्यात, आयात और उनके अंतर का मिलान किया गया है (केंद्रीय रेशम बोर्ड, 2025)।

तालिका 3. रेशम एवं संबंधित उत्पादों का निर्यात–आयात तुलनात्मक विवरण

वित्त वर्ष	निर्यात (₹करोड़)	आयात (₹करोड़)	अंतर (₹करोड़)
2020-21	1466.60	759.75	706.85
2021-22	1848.96	1143.59	705.37
2022-23	1773.38	2284.59	-511.21
2023-24	2027.56	1894.44	133.12
2024-25	2361.75	1561.77	799.98

(स्त्रोतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड 2025, बेंगलुरू)

अंतर = निर्यात – आयात, यह माल–व्यापार अंतर है, निर्यातकों की शुद्ध कमाई या राष्ट्रीय शुद्ध विदेशी मुद्रा की प्रत्यक्ष माप नहीं है। 2022–23 का ऋणात्मक ₹511.21 करोड़ अंतर इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि निर्यात होने के बावजूद उसी वर्ग में आयात अधिक हो सकता है। 2024–25 में सकारात्मक अंतर ₹799.98 करोड़ हो गया, क्योंकि निर्यात बढ़ने के साथ आयात ₹1,894.44 करोड़ से घटकर ₹1,561.77 करोड़ आया। यह आँकड़ा उद्योग की बाह्य व्यापार स्थिति में सुधार का वर्णन करता हैय इससे किसी विशेष योजना या विनिमय दर नीति को सफलता का कारण ठहराना संभव नहीं है। आयात संरचना में कच्चे रेशम का विशेष महत्व हैरू 2024–25 में इसका आयात ₹1,002.03 करोड़ और 2,036 मीट्रिक टन बताया गया है, जबकि 2023–24 में ₹1,254.96 करोड़ और 2,650 मीट्रिक टन था। तुलनात्मक रूप से निर्यातित कच्चे रेशम का मूल्य बहुत कम था।

यह अंतर घरेलू गुणवत्ता, धागे की विशिष्ट मांग तथा विनिर्माण के इनपुट संबंधी प्रश्न उठाता हैय पर आयातित रेशम की वास्तविक उपयोग–श्रृंखला का निष्कर्ष अलग फर्म–स्तरीय अध्ययन से ही निकलेगा।

9. व्यापक वस्त्र क्षेत्र में रेशम की स्थिति वर्गीकरणगत सावधानी

वस्त्र मंत्रालय की व्यापक वस्त्र/ परिधान तालिका में "Silk products" नाम से दिया गया मूल्य केंद्रीय रेशम बोर्ड के "Silk and Silk goods" के विस्तृत समेकित मूल्य से मेल नहीं खाता। उदाहरणतः 2024–25 में पहली श्रृंखला का रेशम निर्यात ₹1,370 करोड़, जबकि दूसरी श्रृंखला का कुल ₹2,361.75 करोड़ है (केंद्रीय रेशम बोर्ड, 2025, वस्त्र मंत्रालय, 2026)। इन आँकड़ों में प्रत्यक्ष अंतर के बावजूद आधिकारिक दस्तावेजों में एक समान उत्पाद–कवरेज या पुल–तालिका उपलब्ध नहीं है, अतः इन्हें परस्पर जोड़ना, एक–दूसरे से घटाना अथवा एक ही निरंतर श्रृंखला की भांति दिखाना उचित नहीं होगा।

तालिका 4. व्यापक वस्त्र रिपोर्ट की रेशम उत्पाद श्रेणी

वित्त वर्ष	रेशम उत्पाद (₹करोड़)	वस्त्र एवं परिधान (₹करोड़)	रेशम उत्पाद का हिस्सा (%)
2023-24	988	282079	0.35
2024-25	1370	304628	0.45
2025-26	2262	309484	0.73

(स्त्रोतः वस्त्र मंत्रलाय भारत, 2026)

इस विशिष्ट ''रेशम उत्पाद'' श्रेणी में 2024–25 से 2025–26 के बीच वृद्धि लगभग 65.11% है। समग्र वस्त्र एवं परिधान निर्यात में इसका अंश लगभग 0.45% से 0.73% हुआ। परिणाम संकेत देता है कि इस सीमित वर्गीकरण में हाल की गति संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र की तुलना में अधिक रहीय पर इस निष्कर्ष को कच्चे रेशम, अपशिष्ट या विस्तृत समेकित निर्यात के सभी घटकों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।

डॉलर में एक अलग प्रकाशित समग्र वस्त्र श्रृंखला 2022–23, 2023–24 और 2024–25 के लिए "silk products" को क्रमशः 94.56, 119.25 और 162.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिखाती है (वस्त्र मंत्रालय, 2025b)। रुपये और डॉलर में साल–दर–साल प्रतिशत का अलग होना स्वाभाविक है, अध्ययन ने आधिकारिक मूल इकाइयां सुरक्षित रखी हैं। वस्त्रों के देश–वार निर्यात आँकड़ों को यहां रेशम–विशिष्ट बाजारों की सूची नहीं माना गया है।

10. चुनौतियाँ और नीति–संबंधी विवेचना

1. उत्पादन से निर्यात तक की गुणवता –श्रृंखला

कच्चे रेशम के आयात का बना रहना बताता है कि घरेलू उत्पादन की कुल मात्रा और निर्यात–उपयुक्त विशिष्ट कच्चे माल की उपलब्धता को अलग समझना आवश्यक है। उत्पादक, देश बुनकर और परिधान–निर्माता के बीच गुणवत्ता मानक, धागे की एकरूपता, परीक्षण एवं ट्रेसबिलिटी पर समन्वय से आयात–निर्भर उत्पादन के विकल्प विकसित हो सकते हैं। किंतु आयात को स्वतः हानिकर मानना भी उपयुक्त नहीं है। यदि आयातित विशेष धागा उच्च–मूल्य निर्यात में प्रयुक्त हो, तो उसका आर्थिक प्रभाव उत्पाद–विशिष्ट अध्ययन से आंका जाना चाहिए।

2. छोटे उद्यम, बाजार और वित्त

कई उत्पादन चरण लघु व्यवसायों, ग्रामीण उद्यमों और पारंपरिक शिल्प से जुड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर की गुणवत्ता शर्ते, कार्यशील पूंजी, समय पर आपूर्ति, परीक्षण, पैकेजिंग तथा व्यापारी के साथ सौदे की जानकारी इन इकाइयों के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। समूह–आधारित खरीद, साझा परीक्षण सुविधा और डिजिटल विपणन के द्वारा निर्यातक तथा उत्पादक के बीच सूचना–अंतर घटाया जा सकता है। स्थानीय डिजाइन एवं क्षेत्रीय पहचान का वाणिज्यिक उपयोग तभी टिकाऊ होगा जब असली उत्पादक तक मूल्य का उचित हिस्सा पहुंचे।

3. सरकारी पहल एव मूल्याकन की आवश्यकता

वस्त्र मंत्रालय (2026) ने रेशम समग्र–2 तथा अन्य वस्त्र ध निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। इन पहलों को उत्पादन की गुणवत्ता, कौशल विकास, ब्रांड संवर्धन तथा बाजार पहुंच के व्यापक नीति संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। यहां किसी योजना से निर्यात में अमुक प्रतिशत वृद्धि होने का दावा नहीं किया गया है, क्योंकि उपलब्ध वार्षिक समष्टि – ऑकड़े कारणात्मक प्रभाव सिद्ध नहीं करते हैं। प्रभाव मूल्यांकन के लिए लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी इकाइयों की तुलनीय लागत, उत्पादन और निर्यात जानकारी चाहिए।

4 . व्यावहारिक सुझाव

उत्पादवार निर्यात एवं आयात का एकरूप नियमित प्रकाशन, कच्चे रेशम के गुणवत्ता–ग्रेड पर उपलब्धता, तैयार वस्तुओं की परीक्षण सुविधाओं का विस्तार, छोटे निर्यातकों को व्यापार दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण, और क्षेत्रीय रेशम उत्पादों

की प्रमाणित पहचान प्राथमिक गतिविधियों हो सकती हैं। निर्यात प्रोत्साहन को केवल कुल बिक्री के लक्ष्य के बजाय स्थानीय मूल्य–वर्धन, भुगतान की विश्वसनीयता और उत्पादक आय जैसे सूचकों से भी परखा जाना चाहिए।

11. सुझाव

1. भारत में पर्यावरण अनुकूल रेशम पालन एवं प्रसंस्करण विधि को प्रसारित करना चाहिए।
2. अंतर्राष्ट्रीय ई–कॉमर्स के माध्यम से रेशम उत्पादन का निर्यात किया जाना चाहिए।
3. अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर गुणवत्ता प्रमाणन व नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे भारतीय रेशम उत्पादन की मांग बढ़ाई जा सकता है।
4. रेशम उद्योग में अच्छी गुणवत्ता विविधता,पारंपरिक कलात्मक वस्त्र आदि की ब्रांडिंग को बढ़ावा देना चाहिए।
5. रेशम पालक व बुनकरों को आधुनिक तकनीक से अवगत करना व उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करनी चाहिए।

12. निष्कर्ष

प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 2020–21 से 2024–25 के बीच भारत के रेशम एवं संबंधित वस्तुओं के समेकित निर्यात मूल्य में वृद्धि हुई, लेकिन 2022–23 में गिरावट भी दर्ज हुई। 2024–25 में कपड़े एवं मेड–अप्स ने लगभग 61.14% तथा तैयार परिधानों ने 20.59% योगदान दिया। उसी वर्ष समेकित निर्यात–आयात अंतर ₹799.98 करोड़ सकारात्मक रहा। इन तथ्यात्मक परिणामों से रेशम निर्यात की संभावनाएं स्पष्ट होती हैं, पर उनका अर्थ यह नहीं कि सकल निर्यात मूल्य के बराबर ही शुद्ध विदेशी मुद्रा बचत हुई।

2025–26 के लिए मंत्रालय की रेशम उत्पाद श्रेणी हाल की वृद्धि दर्शाती हैय उसके दायरे को विस्तृत केंद्रीय रेशम बोर्ड श्रृंखला से अलग रखना विश्लेषण की अनिवार्य शर्त है। भविष्य के अध्ययन में गंतव्य – देशवार रेशम–विशिष्ट व्यापार, निर्यात मात्रा, प्रति इकाई मूल्य, आयातित सामग्री, रोजगार और फर्म–स्तरीय लागत का उपयोग करने से नीति–विषयक निष्कर्ष अधिक सटीक बनेंगे।

13. संदर्भ सूची

1. केंद्रीय रेशम बोर्ड. (2025). Silk exports and imports, 2020–21 to 2024–25 (सांख्यिकीय तालिका; DGCI&S, कोलकाता से संकलित), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार https://www.texmin.nic.in/sites/default/files/Table

2. भारत सरकार. (2025). Economic survey 2024–25: Chapter 7 (आर्थिक सर्वेक्षण). https://www.indiabudget.gov.in/budget2025

3. वस्त्र मंत्रालय. (2025a). Annual report 2024–2025 (वार्षिक रिपोर्ट). भारत सरकार. https://ministryoftextiles.gov.in

4. वस्त्र मंत्रालय. (2025b, 16 दिसंबर). Performance of textile sector पत्र सूचना कार्यालय. https://www.pib.gov.in

5. वस्त्र मंत्रालय. (2026, 28 जुलाई). Promotion of textile export, पत्र सूचना कार्यालय. https://www.pib.gov.in

6. Dasari, J. R., Venkataramana, M. N., & Nandini, H. M. (2024). Revealed comparative advantage analysis of trade of Indian silk and silk products. Journal of Crop and Weed, 20(1), 49-55.